राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 1131/2024

धगाली पत्नी शरवन कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मोटानिया नगर, थाना मतोड़ा,
जिला जोधपुर

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. दूधा राम पुत्र धन्ना राम, निवासी मोटानिया नगर थाना मतोड़ा, जिला जोधपुर।
3. ओमा राम पुत्र पोकर राम, निवासी मोटानिया नगर थाना मतोड़ा, जिला जोधपुर।
4. चूना राम पुत्र धन्ना राम, निवासी मोटानिया नगर थाना मतोड़ा, जिला जोधपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री रामनिवास हनिया
प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

20/09/2024

1. याचिकाकर्ता यहां आपराधिक अपील संख्या 22/2022 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 17.02.2024 के अपीलार्थी आदेश के खिलाफ है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई थी और ग्राम न्यायालय, ओसिया, जिला जोधपुर के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.03.2022 को पारित निर्णय और सजा को बरकरार रखा गया था, जिसके तहत आरोपियों को

धारा 447 और 427 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन आईपीसी की धारा 323/34 के तहत दोषी/दंडित किया गया था।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि 21 दिसंबर, 2016 को याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके घर पर ट्रैक्टर पर आए। उन्होंने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसके साथ मारपीट की, उसके गहने चुरा लिए और उसकी गरिमा से समझौता किया। जब उसके भाई पप्पू राम और अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो उन पर भी हमला किया गया। आईपीसी की धारा 447, 427 और 323/34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया गया और ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

2.1 29 मार्च, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को धारा 447 और 427 के तहत आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें धारा 323/34 के तहत दोषी ठहराया। इस परिणाम से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने अपीलीय अदालत में अपील की, जिसने 17 फरवरी, 2024 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दोनों निर्णयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने में विफल रहा। पीडब्लू-7 ने विशेष रूप से यह गवाही दी कि धगली देवी को एक कुंद हथियार से कई चोटें आईं, जैसा कि चोट रिपोर्ट (प्रदर्श 7) में विस्तृत है। इसके अलावा, पीडब्लू-1 से पीडब्लू-5 के बयानों से पुष्टि होती है कि अभियुक्तों ने याचिकाकर्ता को चोटें पहुंचाईं और क्रूरता से काम किया। हालांकि, निचली अदालतों ने इन गवाहों की गवाही पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया।

3.1 याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि अभियुक्तों- दुधा राम, चूना राम और ओमा राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 लगाई जानी चाहिए थी और अब यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि यह आरोप जोड़ा जाए।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रत्यक्षदर्शी रामा राम पर गलत तरीके से अविश्वास किया गया है, इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं लगता कि उक्त गवाह को शिकायतकर्ता द्वारा प्रासंगिक समय पर किए जाने वाले कुछ कार्यों के लिए नियोजित किया गया था। एक कर्मचारी होने के नाते, शिकायतकर्ता द्वारा दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसलिए, इस बात से इंकार नहीं किया

जा सकता है कि वह पूरी तरह से प्रेरित और इच्छुक गवाह है और उसने शिकायतकर्ता द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर गवाही दी है।

6. याचिकाकर्ता दूधा राम, चूना राम और ओमा राम के खिलाफ धारा 354 के तहत आरोप जोड़ने के लिए परीक्षण चरण में या यहां तक कि विद्वान अपीलीय अदालत के समक्ष कोई भी आवेदन आदि पेश करके कदम उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने में विफल रहा। मुझे वर्तमान याचिका में इस तरह के आरोप जोड़ने के निर्देश के लिए कोई औचित्य नहीं दिखता।

7. मैं विद्वान परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं।

8. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

9. याचिका खारिज की जाती है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।